भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1445
बुधवार, 12 मार्च, 2025 (21 फाल्गुन, 1946 (शक)) को उत्तरार्थ

डेयरी और मत्स्यपालन सहकारी समितियों के साथ-साथ 10,000 नव स्थापित एम-पीएसीएस

1445# श्री बंशीलाल गुर्जरः

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (एम-पैक्स) मॉडल को और विस्तारित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन नव स्थापित सहकारी समितियों से कितने किसानों, डेयरी उत्पादकों और मछुआरों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होने की अपेक्षा है; और

(घ) इस पहल को ग्रामीण विकास के व्यापक लक्ष्यों से किस प्रकार जोड़ा जाएगा?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख): सरकार ने दिनांक 15.02.2023 को देश में सहकारी समितियों के सशक्तिकरण और इसकी पहुंच को जमीनी स्तर तक पहुँचाने की योजना को अनुमोदित किया है । इस योजना में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB), और राज्य सरकारों के सहयोग से भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं जैसे कि डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (DIDF), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), इत्यादि के अभिसरण से पांच वर्षों में देश के सभी पंचायतों/गांवों को कवर करने के लिए 2 लाख नई बहुउद्देशीय पैक्स (एम-पैक्स), डेयरी, मात्स्यिकी सहकारी समितियां स्थापित करना शामिल है ।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार दिनांक 15.2.2023 को योजना के अनुमोदन के बाद देश भर में दिनांक 27.1.2025 तक कुल 12,957 नई पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियां पंजीकृत की जा चुकी हैं।

(ग) और (घ): 'सरकार के समग्र' दृष्टिकोण का लाभ उठाकर ये प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियां अपने व्यावसायिक कार्यकलापों में विविधता लाने के लिए आवश्यक अवसंरचना जैसे दुग्ध परीक्षण प्रयोगशालाओं,

थोक दुग्ध कूलरों, दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, बायोफ्लॉक तालाबों, मत्स्य कियोस्क का निर्माण, हैचरी का विकास, आदि की स्थापना और आधुनिकीकरण कर सकती हैं ।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार लगभग 13 लाख किसान नवस्थापित पैक्स से जुड़े हैं, लगभग 3 लाख और 33,000 किसान क्रमशः नवस्थापित डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों से जुड़े हैं ।

इन कृषक सदस्यों को अपने उत्पाद के विपणन, अपने बाज़ार का साइज़ बढ़ाने, अपनी आय में वृद्धि करने, ऋण सुविधाएं प्राप्त करने और ग्राम स्तर पर ही अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए अपेक्षित फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप संतुलित क्षेत्रीय विकास होता है । नई व्यवहार्य बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन होता है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव पड़ता है, जो ग्रामीण विकास में योगदान देता है ।

******